श्री संघप्रिय गौतमः सर, हरियाणा में होता है गयाराम ग्रौर ग्रायाराम, हरियाणा में...(इपवधान)...

श्री गया सिंह: सभापति महोदय. ग्रभी जो उन्होंने बताया, माइनिंग इंड-स्ट्रीज हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ग्रीर यह मुख्य रूप से पिछड़े हुये ट्राइबल्स एरिया में है, लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने बताया पाइनिंग इंडस्ट्रीज में श्राजादी के बाद कई एरिया में हमारा विकास हम्रा, उसका प्रोस्पेक्टिंग हम्रा । प्रभी काफी डिप हो गया ग्रौर बगल में में उसके विकास के लिये जो कई ग्राइटम्स हैं, वह नहीं कर रहे हैं श्रौर जैसा श्रभी माननीय सदस्य ने कहा हम ज्यादा प्रभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं काफी सस्ते में ग्रीर दूसरी ग्रोर ह : इंपोर्ट कर रहे हैं सेम मेटेरियल, सेम ग्रेड का मेंटेरियल, कई इंडस्ट्रीज में जहां रा-मैटेरियल है वह काफी महंगे में ह इंपोर्ट कर रहे हैं भौर देश के ग्रन्दर प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं । इसलिये मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, खासतौर से स्टील इंडस्ट्रीज में हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं भीर हमारे यहां कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जिनका विकास नहीं कर रहे हैं, तो ग्राप उस ग्रोर क्या ध्यान दे रहे हैं? दूसरी श्रोर बिहार की कई ऐसी इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज तो काफी डिप हो गई सिंहभूमि में, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन किया था ग्रापसे ग्रौर श्राज बगल में वह जो है, माइनिंग इंडस्टी मिली है वहां, चार साल से भ्राप सोच रहे हैं, उस को चालू नहीं किया।

भी बलराम सिंह यादव : मान्यवर, स्टील के बारे में तो में जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिये कि हमारा विषय नहीं है। मगर, इतना जरूर मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इधर जो हम नई पालिसी ला रहे हैं या एम०एम० ग्रार० डी० एक्ट में हम जो संशोधन लाने पर विचार कर रहे हैं, उनकी भावनाग्रों, का जब हम निर्णय लेंगे तो जरूर उनकी भावनाग्रों का ध्यान रखेंगे;

*166. [The Questioner (Shrimati Basanti Sarma, was absent. For answer, vide col......infra.]

Text Books for IX Standard in West Bengal

*167 SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOP-MENT be pleased to state:

- (a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem which appeared in the "Telegraph" (Cal.) of February 8, 1993 under the caption "Commercial bias in West Bengal textbook" referring to "Hindustan Ki Tareekh" prescribed for class IX by West Bengal Board of Secondary Education for Urdu medium schools in the State which contains derogatory remarks against Guru Tegh Bahadur; and
- (b) If so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) A statement is laid on the table of the Sabha.

Statement

Text Books for IX Standard in West Bengal

As per information received from the Government of West Bengal, the book entitled 'Hindustan Ki Tarrekh' referred to in the news item appearing in the newspaper 'The Telegraph' dated 8.2.93, has not been approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a textbook. Both the NCERT and the National Steering Committee set up by the Ministry of Human Resource Development to review the school textbooks from the standpoint of national integration have opined that the book presents an inaccurate and distorted version of many aspects of medieval history.

The National Steering Committee has, in its meeting held on 30-31-1.93 recommended, inter alia that textbooks which are not authorised should not be allowed to be used in

. the schools, including those run by private bodies or religious or cultural organisations. The Committee's report containing its récommendations placed before the Conference of State Education Ministers and Educationists held in New Delhi on 1.2.1993. As per the decision taken in the Conference, views of the State/UT Governments on the report have been invited for evolving a plan of both for the Central Government and the State|UT Governments to protect the secular and national character of school textbooks and other educational material.

श्री जगरीश प्रवाद माथुर: श्री जन् यह बडा गंभीर सवाल है, यह सदन में पहले भी उठ चुका है, इस पुस्तक में गुरु तेग वहादुर: शिवाजी र ण प्रताय के लिए श्रपमानजनक शब्द कहे गए हैं। में यह पूछा चाहता हूं, समय बहुत कम है, कि श्रापने यह गोलमाल जवाब दिया है, श्राखिर में कहा है श्रापने—

"As per the decision taken in the Conference, views of the State/UT Governments on the report have been invited for evolving a plan of action both for the Central Government and the State/UT Governments..."

श्रापने यह नहीं बताया कि क्या प्रदेश सरकार से ग्रापने इस पुस्तक के लिखने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की या नहीं की है? ...(व्यक्ष्यन)

भी मोहम्मद सलीम : यह यू०पी० भोडे ही है। ...(व्यवधःम)...

श्री जगदोश प्रसाद माथुर : क्या श्रापने पं० बंगाल सरकार से कहा है कि जिसने कित्य किखी है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए ? श्रीर, जो किनावें पढ़ाई जा रही हैं, जिसमें गुरु तेग बहादुर, शिवाजी श्रीर राणा प्रताप का है, श्रापने लिखा है कि नैरोगेट, यह खराब है, तो श्रापने कार्यवाही करने की मांग की है था नहीं की ? नहीं की तो क्यों नहीं की ?

श्री अर्जुन सिंह: श्रादरणीय सभापित जी, इसमें बहुत साफ रूप से उत्तर दिया गया है कि यह पुस्तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एप्रव्ड पुस्तक नहीं है श्रीर इसलिए जो पुस्तक एप्रव्ड तही है उसका इस्तेमाल हो । नहीं चाहिए । इस श्रोर पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान श्राकित किया गया है श्रीर वह इस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगी ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: उस लेखक के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Allocation of Iron and Steel to Gujarat

*163. SHRI RAJUBHAI A. PAR-MAR: Will the Minister of STEEL be pleased to state the steps taken or proposed to be taken to streamline the system of allocation of iron and steel to Gujarat?

MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): After deregulation of pricing and distribution of iron and steel w.ef. 16th January, 1992, the requirements of only five sectors; namely; Defence; Railways, Exporters of Engineering Goods Small Scale Sector and North Eastern, Region are being met on priority. The Development Commissioner for Iron and Steel (DCI&S) makes allocation of pig iron to the five designated priority sectors. He also allocates engineering to exporters of goods, small scale sector and the North-Eastern region. The requiremen's of the States including Gujarat are duly taken into account by the DCI&S in making allocations of pig iron and steel. Requirements of other consumers are met by Main Producers in accordance with their distribution guidelines.